ट्रेड रेगुलेशन के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेगी सरकार

शुगर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट की लिमिट जल्द खत्म होगी!

[ऋतुराज तिवारी *नई दिल्ली*]

सरकार शुगर के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर क्वांटिटेटिव प्रतिबंध हटाने का प्लान बना रही है। शुगर सेक्टर के लिए नई पॉलिसी के तहत सरकार इसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेगी। फूड मिनिस्ट्री के एक अफसर ने बताया, 'हमें स्टेबल एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी की जरूरत है।' इस प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिपार्टमेंट के अफसरों की बैठक हुई थी।

इस साल सितंबर तक ओपन जनरल लाइसेंस के तहत बगैर लिमिट के शुगर एक्सपोर्ट्स की इजाजत मिली थी। लेकिन 1 अक्टूबर से शुरू नए सीजन के लिए नई इजाजत नहीं मिली है। हालांकि 10 पर्सेंट की ड्यूटी पर व्हाइट और रॉ शुगर का इंपोर्ट हो सकता है।

अफसर ने बताया, 'ग्लोबल शुगर प्राइस के 650 डॉलर प्रति टन से घटकर 510 डॉलर प्रति टन पर आ जाने से सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकती है। शुगर के ग्लोबल प्राइस बढ़ने पर अत्यधिक एक्सपोर्ट पर अंकुश लगाने के लिए हम एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा सकते हैं।' इस साल सिंतबर तक भारत ने 34 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट किया। लगातार तीसरे साल सरप्लस प्रोडक्शन से एक्सपोर्ट के मौके खुले हैं। अफसर ने बताया, 'गन्ने और शुगर के प्रोडक्शन का जायजा लेने के बाद जनवरी में एक्सपोर्ट पर फैसला हो सकता है।' उधर, देश में शुगर के सस्ते इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए शुगर इंडस्ट्री ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की गुहार लगाई है।

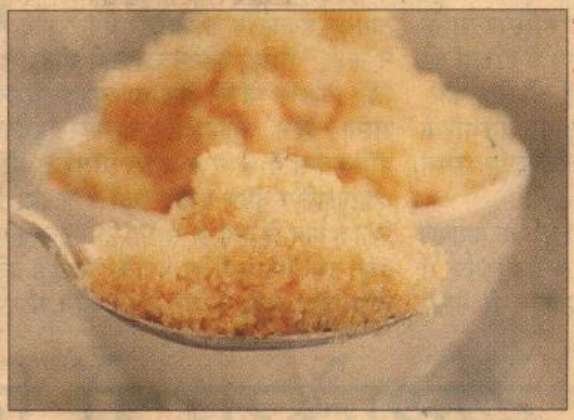

> "हमारा मानना है कि शुगर मिलों की लागत बचाए रखने और किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शुगर (व्हाइट और रॉ दोनों) के सस्ते इंपोर्ट पर अंकुश लगाना ही एकमात्र उपाय है। मौजूदा ड्यूटी पर शुगर ट्रेडर के लिए इम्पोर्ट करना फायदेमंद है
>
> **एम श्रीनिवासन,** इस्मा के प्रेसिडेंट

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 60 पर्सेंट करने का प्रस्ताव किया है। वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से आने वाली शुगर से देश की परेशानी बढ़ गई है। यह इंडियन शुगर से 5-6 रुपए किलो सस्ता है।

नए प्रपोजल पर चर्चा शुरू

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी के नए प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड डिपार्टमेंट के अफसरों की बैठक हुई थी

इस्मा के प्रेसिडेंट एम श्रीनिवासन ने बताया, 'हमारा मानना है कि शुगर मिलों की लागत बचाए रखने और किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शुगर (व्हाइट और रॉ दोनों) के सस्ते इंपोर्ट पर अंकुश लगाना ही एकमात्र उपाय है। मौजूदा ड्यूटी पर शुगर ट्रेडर के लिए इम्पोर्ट करना फायदेमंद है।'

इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में शुगर के डीकंट्रोल पर रंगराजन कमेटी की सिफारिशों पर भी चर्चा हुइ। मौजूदा रेगुलेटेड मैकेनिज्म को हटाने के मसले पर भी बैठक में बातचीत हुई।

फूड मिनिस्ट्री के दूसरे अफसर ने बताया, 'चार महीने में कितनी शुगर की बिक्री होगी इसका फैसला अभी सरकार करती है। इसकी समयावधि बढ़ाकर छह माह की जाएगी। उसके बाद इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसका भी फैसला पूरी तरह से शुगर मिलों पर छोड़ दिया जाएगा।'